

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.11(2)चिस्वा/2/2020

जयपुर, दिनांक : 11.2.2020

परिपत्र

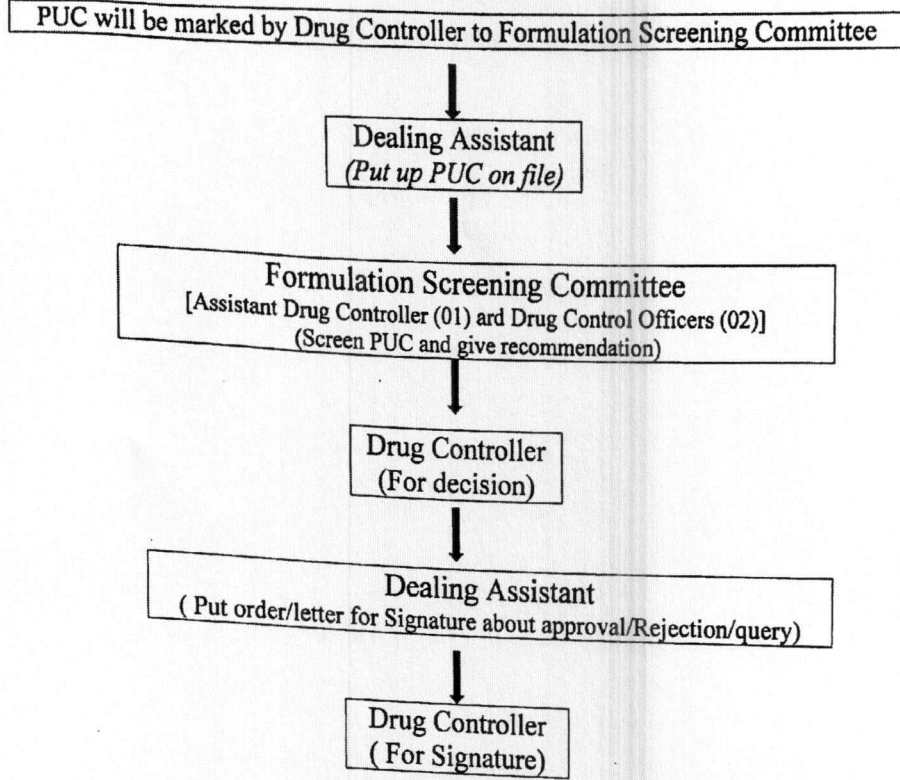
औषधि नियंत्रण संगठन द्वारा निश्चित समयावधि में सेवा प्रदान करने, प्रक्रिया को आसान करने व औषधि निर्माण ईकाईयों के राज्य में निवेश को आकर्षित करने की दृष्टि से औषधि निर्माताओं के लाईसेन्स/प्रोडक्ट परमिशन/ब्लड बैंक/ब्लड स्टोरेज इत्यादि के संबंध में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण निम्नानुसार निर्धारित अवधि में किया जावे:-

S.No.	Services	Time Frame (No.of working days)
1	Grant of Manufacturing Licence/Blood Bank Licence/Testing Laboratories Licence	
	Inspection	10 days
	Shortcoming Rectification-Verification	07 days
	Screening of Products	03 days
	Processing and granting of licence	01 days
	Total Time	21 days
2	Renewal of Blood Bank Licence	15 days
3	Grant of permission for Blood Storage Centre	15 days
4	Approval of Product Permission	03 days
5	Approval of Technical Staff (Constitution of Board for approval)	15 days
6	Issue of test licences	05 days
7	Recommending for Grant/renewal of licences to central licensing authority, Delhi with respect to Vaccines and Sera; Large Volume Parental /Notified Medical Device	30 days
8	Effecting changes in existing mfg licences	15 days
9	Issue of Free Sale Certificate	05 days
10	Issue of Market Standing Certificate	05 days
11	Issue of GMP/GLP certificate	05 days
12	Issue of Non Conviction Certificate	05 days
13	Issue of Production Capacity Certificate	05 days
14	Issue of WHO GMP certificate	15 days
15	Issue of Licence Validity Certificate	07 days
16	Issue of Certificate Of Pharmaceutical Products (COPP)/ Export NOC	15 days
17	Issue of Neutral Code Certificate	07 days
18	Issue of Quality and Capacity Certificate	07 days
19	Issue of Performance Certificate	07 days

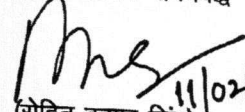
Mr

1. औषधि नियंत्रण संगठन में प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट परमिशन के आवेदनों हेतु पत्रावलियों का Processing Channel का फ्लो चार्ट निम्नानुसार होगा:-

Flow Chart



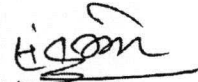
2. जिन आवेदनों पर अग्रिम कार्यवाही के तहत सीडीएससीओ के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण की आवश्यकता हो, उनके सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर एक कार्य दिवस में ही सीडीएससीओ को सूचना दी जायेगी तथा उनके साथ समन्वय स्थापित कर निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी।
3. उक्त आवेदनों के निस्तारण की अवधि को विभागीय वेबसाइट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जावे एवं इसका समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
4. निर्धारित अवधि से अधिक समय तक पत्रावली लम्बित रखने पर सम्बन्धित लाईसेन्सिंग अथॉरिटी का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जायेगा। अतः सम्बन्धित लाईसेन्सिंग अथॉरिटी अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों के पास संधारित होने वाले पत्रावलियों का समयबद्ध निस्तारण/प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करेंगे।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।

5. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि नये/नवीनीकरण लाईसेन्स आवेदन के प्रकरणों में सीडीएससीओ के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण की आवश्यकता हो, उन प्रकरणों में प्राथमिकता के साथ अधिकारियों की नियुक्ति कराने का श्रम करावें।
6. औषधि नियंत्रक (प्रथम/द्वितीय), औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मुख्यालय स्तर पर आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु मुख्यालय पर पदस्थापित एक सहायक औषधि नियंत्रक एवं 2 औषधि नियंत्रण अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए चार Formulation Screening Committee का गठन कर पालना रिपोर्ट इस विभाग को प्रस्तुत करेंगे तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा उन्हें एल्फाबेटिकली कार्य का आवंटन किया जायेगा।
7. समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
8. समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभाग की बैवसाईट पर अपलोड करवावें।
10. अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान फार्मास्यूटिकल मेनुफेक्चरर एसोसियेशन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपकी संस्था के सभी सदस्यों के साथ-साथ अन्य राज्य के औषधि एवं कॉस्मेटिक निर्माताओं को अवगत करावे जिससे राज्य में औषधि एवं कॉस्मेटिक इकाईयों में बढ़ोतरी हो सके।



(संजय कुमार)
शासन उप सचिव